भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 692

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्वास्थ्यचर्या सुविधाओं संबंधी अध्ययन

†692. **श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ समन्वय से वर्ष 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 2 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्यचर्या सुविधाओं के कामकाज संबंधी अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एनएचएम के अंतर्गत लगभग 80 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अवसंरचना, कार्मिक बल और उपकरणों संबंधी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने में विफल रही हैं; और
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भर्ती सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है।

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) आवश्यक मानक हैं जो जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से न्यूनतम आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2007 में विकसित और वर्ष 2012 और वर्ष 2022 में संशोधित, ये मानक हाल की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के अनुरूप हैं और हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए मौलिक हैं। आईपीएचएस दिशा-निर्देश राज्यों को महत्वपूर्ण मानकों की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है।

मंत्रालय ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित सभी स्तरों के सुविधा केन्द्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन की सुविधा के लिए दिनांक 28 जून 2024 को आईपीएचएस के तहत एक ओपन-सोर्स टूलकिट और एक वेब-आधारित डैशबोर्ड (www.iphs.mohfw.gov.in) विकसित किया है। आईपीएचएस डैशबोर्ड को आईपीएचएस 2022 मानकों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के अनुपालन की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करता है, जिससे अंतराल की पहचान करने और समय पर अंतक्षेप की सुविधा के लिए निरीक्षण और डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

दिनांक 22 जनवरी, 2025 तक - 93% स्वास्थ्य सेवा सुविधा केन्द्रों का आईपीएचएस के लिए मूल्यांकन किया जा चुका है। कुल मूल्यांकित सुविधा केन्द्रों में से 55% सुविधा केन्द्रों ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

*****